प्रदेश में चलेगा राजस्व महाभियान

सीएम ने खजुराहो में राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान दिये निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 8 दिसंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों और आम नागरिकों के भूमि-संबंधी लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महाभियान पुन: चलाया जाए.

इससे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अभिलेखों में सुधार जैसे प्रकरणों का तेजी से और पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को महाराजा कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में राजस्व विभाग की समीक्षा कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ.

यादव ने निर्देश दिए कि 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें. इसके लिए प्राथमिकता से पीठासीन अधिकारियों से संपर्क करें.

राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए. नागरिकों को उनकी भूमि का त्वरित नक्शा और विवरणों की उपलब्धता आसान बनाए. इसके लिए वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध करायें. यह सुविधा अगले दो वर्ष में पूर्ण करें. वेबसाइट से प्राप्त दस्तावेजों को प्रामाणिक बनाए जिससे दस्तावेजों की डुप्लीकेसी रुकेगी. नवीन आवश्यक आबादी भूमि का चिन्हांकन करें. प्रदेश के नक्शाविहीन ग्रामों का नक्शा बनाएं.

अगले तीन वर्ष के लिये ये होगी कार्य योजना

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अनुरूप विभागीय पोर्टल का आधुनिकीकरण किया जाएगा.
- नक्शाविहीन ग्रामों के नक्शे बनाने तथा भू-अर्जन प्रक्रियाओं को एंड-टू-एंड ऑनलाइन किया जाएगा.
- नवीन आवश्यक आबादी भूमियों का चिन्हांकन किया जाएगा.
- विश्वास आधारित डायवर्जन प्रक्रिया लागू करने की योजना है.

राशन दुकानों में पीओएस मशन लगेगी

भोपाल. राशन वितरण व्यवस्था को अधिक तेज और पारदर्शी बनाते हुए उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाई जाएगी, जिसमें पीओएस मशीन से तौल कांटे का इंटिग्रेशन एवं आईरिस स्केनर का प्रावधान है. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्मार्ट पीडीएस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा. इसके अलावा शासकीय गोदामों की छत पर सोलर पैनल लगाने, भण्डारण प्रक्रिया का मॉर्डनाइजेशन और गोदामों का अपग्रेडेशन करने के साथ उन्नत तकनीकी की सहायता से विभिन्न स्तरों पर डेटा सिंक्रोनाइजेशन के कार्य भी किए जाएंगे. यह जानकारी सोमवार को खजुराहो में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा के दौरान अगले तीन वर्ष के रोडमैप के प्रजेंटेशन के दौरान दी गई. बैठक में सिंहस्थ-2028 के लिए खाद्यान्न सामग्री के वितरण के लिए तैयार की गई योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि खाद्य विभाग, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन सहयोग से समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. अखाड़ों की मांग के अनुसार अस्थायी राशन कार्ड जारी किया जाएगा. साथ ही, मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना की जाएगी. यह व्यवस्था सुचारू रहे इसलिए मेला क्षेत्र को 8 जोन और 16 सेक्टर में विभाजित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारण के लिए गोदामों की स्थापना की जाएगी. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए कि हर पात्र हितग्राही तक खाद्यान्न वितरण का लाभ सुगमता से पहुंचे.

Rani Dullaiya Smriti Ayurved PG College & Hospital

Barkhedi Kalan, Bhadbhada Road, Bhopal. Tel. 0755-2696776
Website: www.rdmayurvedcollege.org, Email. rdayurved@gmail.com

Recognized by National Commission for Indian system of Medicine, New Delhi
Affiliated to Madhya Pradesh medical Science University, Jabalpur, M.P.
Vacancies for BAMS (UG) and M.D./M.S. Ay (PG) as per the NCISM Norms

Department	Professor	Associate	Assistant
1.Samhita and Siddhanta	01	01	01
2. Rachana Shareer	02	03	02
3. Dravyaguna	02	02	-
4. Panchakarma	02	01	02
5. Agadatantra	02	01	01
6. Swasthavritta and Yoga	01	01	01
7. Shalyatantra	-	02	02
8. Kaumarbhritya	01	02	02
9. Kayachikitsa	01	01	01
10. Shalakyatantra	01	03	02
11. Kriya Shareer	01	01	01
12. Roga Nidan	01	03	02
13. Prasutitantra	-	01	02
14. Rasashastra	-	01	-

Qualification : As per the National Commission for Indian system of Medicine (Minimum essential standards, assessment and rating for undergraduate Ayurveda colleges and attached teaching hospitals) Regulations, 2024.
Salary : Negotiable
Candidate should send their bio-data along with self-attested required documents as early as possible in person or mail to **rdayurved@gmail.com**
FOR MORE DETAILS CONTACT : Ph:. 0755-2696776, 9826524247

सीएम ने दिखाई 10 नई कैंटर बसों को हरी झंडी

पन्ना, 8 दिसंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क के मड़ला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इन बसों के जरिए पर्यटक जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव और अधिक सुविधा जनक तरीके से ले सकेंगे. इन कैंटर बसों में एक साथ 19 पर्यटकों के बैठने की क्षमता है. यह बसें अन्य सफारी वाहनों की तुलना में अधिक लंबी और ऊंची हैं, जिससे पर्यटकों को बेहतर दृश्य और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा. बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बसें अधिक सुरक्षित मानी जा रही हैं. इन बसों की लंबाई और ऊंचाई भी अधिक है, जिससे सफर के दौरान पर्यटकों को ज्यादा जगह और आराम मिलता है.

ऑनलाइन बुकिंग न होने पर पर्यटकों को मिलेगी पार्क राउंड की सुविधा :- 10 नई वीविंग कैंटर बसों के संचालन से उन पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी, जो पहले ऑनलाइन बुकिंग न होने की वजह से जंगल सफारी का अनुभव नहीं ले पाते थे. इसके साथ ही ऑनलाइन स्लॉट जल्दी भर जाने से कई पर्यटक नेशनल पार्क पहुंचकर भी सफारी से वंचित रह जाते थे.

धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा व्यवस्था को किया उजागर

स्कूल शिक्षा बजट 37,000 करोड़ रुपये हो गया : पटवारी

विशेष संवाददाता

भोपाल,08 दिसंबर. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक तीखी पत्रकार वार्ता में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर गम्भीर आरोप लगाए.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सच बोलकर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जर्जर स्थिति को उजागर किया है. पटवारी के अनुसार, मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश के 50 लाख से अधिक बच्चों ने सेब जैसे साधारण फल का नाम तक नहीं सुना जो स्कूलों की दुर्दशा और गहराते संकट का संकेत है. पटवारी ने राष्ट्रीय एजेंसियों और शोध संस्थानों की उन रिपोर्टों का हवाला दिया, जिनमें शिक्षा, पोषण, गरीबी और बाल कल्याण से जुड़े गंभीर आंकड़े वर्षों से सामने आते रहे हैं.

> पटवारी ने यह भी सवाल उठाया कि जब सात वर्षों में स्कूल शिक्षा बजट 7,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 37,000 करोड़ रुपये हो गया है, तब भी मध्याह्न भोजन अपर्याप्त क्यों है, हजारों स्कूलों में प्राचार्य क्यों नहीं हैं, और 1,400 से अधिक स्कूल एक शिक्षक पर क्यों निर्भर हैं? स्थिति को उपेक्षा और भ्रष्टाचार का महाघोटाला बताते हुए पटवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रधान की टिप्पणी ने भाजपा सरकार की पोल खोल दी है. उन्होंने सरकार से तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की और पूछा कि क्या सरकार इन अनियमितताओं पर सीबीआई या ईडी जांच कराएगी. पटवारी ने कहा, यह राजनीति नहीं है. यह 56 लाख बच्चों के भविष्य का प्रश्न है. अब खामोशी चलने वाली नहीं.

पेज एक का शेष

81 विस क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्षेत्र होंगे विकसित

1.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों का फार्मलाइजेशन किया जाएगा और उन्हें उद्यम पोर्टल से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि अगले तीन वर्ष में 5 हजार से अधिक करोड़ की प्रोत्साहन राशि एमएसएमई इकाइयों को दी जाएगी. इसी तरह क्लस्टर विकास के लिए 30 नए निजी क्लस्टरों और 22 सामान्य सुविधा केंद्रों को स्वीकृति दी गई है. 31 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आगामी वर्षों में 6,000 से अधिक भूखंडों के आवंटन की योजना बनाई गई है. 100 औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी की स्थापना की जाएगी, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को पर्यावरणीय संतुलन के साथ बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमएसएमई विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के दृष्टिगत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को उद्योग जगत के बीच इस तरह से प्रचारित और प्रस्तुत करें.

विवाह से पहले कोई बीमारी की जानकारी छुपाना क्रूरता

हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में दिए आदेश

जबलपुर,8 दिसंबर. हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि विवाह पूर्व बीमारी छुपाना और बीमार करने की साजिश करने का आरोप लगाना क्रूरता श्रेणी में आता है. दूसरा पक्ष अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर टेंशन में रहते हुए ज़िंदगी भर परेशान रहेगा.

उसे आर्थिक तथा इमोशनल नुकसान उठाना पड़ा. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट तथा जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ ने कुटुम्ब न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता पति के पक्ष में ज्यूडिशियल सेपरेशन के आदेश जारी किये है. मंडला निवासी डॉ महेन्द्र कुशवाहा की तरफ से दायर की गयी अपील में कुटुम्ब न्यायालय के द्वारा ज्यूडिशियल सेपरेशन के आवेदन को निरस्त करते हुए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश जारी किये जाने को चुनौती दी गयी थी. अपील में कहा गया था कि उसकी अनावेदिका से अरेंज मैरिज हुई थी. विवाह के पूर्व अनावेदिका को मिर्गी के दौरे आते थे, इस बीमारी के संबंध में उसे जानकारी नहीं दी गयी थी.

उसे थायराइड की बीमारी के संबंध में बताया गया था. अनावेदिका को जून व जुलाई 2022 में मिर्गी के दौरे आये थे. जिसके बाद पति ने उसे छोड़ दिया था और ज्यूडिशियल सेपरेशन के लिए कुटुम्ब न्यायालय में आवेदन किया था. ज्यूडिशियल सेपरेशन के आवेदन की सुनवाई के दौरान अनावेदक पत्नी ने इस बात से साफ इंकार कर दिया कि वह मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है. उसने अपने पति व सास पर बदनीयती से बीमार करने उसे बहुत मीठा खाना दिये जाने के आरोप लगाये थे. अनावेदक पत्नी की तरफ से तर्क दिया गया कि ज्यूडिशियल सेपरेशन की इजाज़त दी जाती है तो इससे उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी.

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री भजन लाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

देश-दुनिया में जिन्होंने बढ़ाया मान उनके स्वागत में तैयार है राजस्थान

हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई-बहनों ने अपनी कुशलता और कर्मठता से देश-विदेश में नाम कमाया और राजस्थान की धरती को गौरवान्वित किया।

प्रवासियों को राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने हर वर्ष 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' के आयोजन की पहल की।

प्रवासी राजस्थानी दिवस का पहला आयोजन 10 दिसम्बर 2025 को जयपुर में किया जा रहा है। प्रवासियों के साथ हमारे इस रिश्ते को मज़बूत करने में यह आयोजन एक अहम कड़ी है।

प्रवासी राजस्थानी दिवस
10 दिसम्बर 2025 • जयपुर

प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान सरकार की पहल

- प्रवासी राजस्थानियों हेतु नए विभाग का गठन
- राजस्थान फाउण्डेशन के 14 नए चैप्टर गठित, 12 पुराने चैप्टर्स को किया सक्रिय
- नई प्रवासी राजस्थानी नीति

प्रवासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए 8 विशेष सत्र

- प्रवासी राजस्थानी संवाद
- उद्योग
- शिक्षा
- जल संसाधन
- नवीन एवं अक्षय ऊर्जा
- स्वास्थ्य
- पर्यटन
- खनन

2 साल
नव उत्थान - नई पहचान
बढ़ता राजस्थान - हमारा राजस्थान

आयोजक
Rajasthan Foundation
BIP RAJASTHAN
RIICO GROW WITH RAJASTHAN

इंडस्ट्री पार्टनर
CII Confederation of Indian Industry

राजस्थान संवाद

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14